व्राप्ता ।

संख्या- 5 4 - / xxxvi(2)/2013-2-सात(ई) / 2008

डी०पी० गैरोला, प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

न्याय अनुमाग-2

देहरादून : दिनांक : 21 फरवरी, 2013

विषय- जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील प्रतापनगर में स्थापित सिविल जज (जू०डि०) के न्यायालय हेतु सृजित अस्थाई पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या— 60/xxxvi(2)/2012-2—सात(ई)/2008, दिनांक 8—2—2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील प्रतापनगर में स्थापित सिविल जज (जू०डि०) के अस्थाई न्यायालय के लिये स्वीकृत सभी अस्थाई पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाए, दिनांक 1—3—2013 से 28—2—2014 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त न्यायालय/पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या—13/xxxvi(2)2010-10-सात—ई/08, दिनांक 11—11—2010 द्वारा किया गया था।

- 2— उक्त न्यायालय के कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्ते सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होगी।
- 3- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश-00 के नामें डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या— ए—1—1270/76—दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या— ए—2—877/दस—92—24(8)/92 दिनांक 7—11—92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किए गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।

(डी०पी०-मेरोला प्रमुख सचिव,

संख्या- 54/xxxvi(2)/2013-2-सात(ई)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।

2- जिला न्यायाधीश / जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

3- सिविल जज (ज्०डि०) प्रतापनगर, जिला टिहरी गढ़वाल।

4- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

प्रिमेन्द्र सिंह अधिकारी) संयुक्त सचिव,